पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम

वैश्विक मंदी के बीच भारत का आर्थिक पराक्रम

वर्ष 2014 में जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभाली थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था नीतिगत पंगुता और निवेशकों के गिरते भरोसे के चक्रव्यूह में फंसी थी, परंतु पिछले 12 वर्षों (2014 से 2026) में सरकार के साहसिक नीतिगत फैसलों, कड़े सुधारों और दूरदर्शी आर्थिक विजन ने भारत को दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है। आज जब अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं मंदी, उच्च ब्याज दरों और ढांचागत संकट से जूझ रही हैं, तब भारत वैश्विक विकास के सबसे मजबूत इंजन के रूप में चमक रहा है। निरंतर 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए रखते हुए भारत आज लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर के पड़ाव के अत्यंत निकट पहुंच चुका है। टैक्स स्लैब में ऐतिहासिक राहत, जीएसटी 2.0 का सफल क्रियान्वयन, शेयर बाजार का अभूतपूर्व वैल्थ क्रिएशन और डोमेस्टिक रिटेल इनवेस्टर्स का बढ़ता भरोसा देश की आर्थिक संप्रभुता के नए स्तंभ हैं। यह विशेष ऐडवर्टोरियल इस बात का प्रामाणिक विश्लेषण है कि कैसे नीतिगत निरंतरता और 'नेशन-फर्स्ट' आर्थिक नीतियों के दम पर भारत एक आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है।

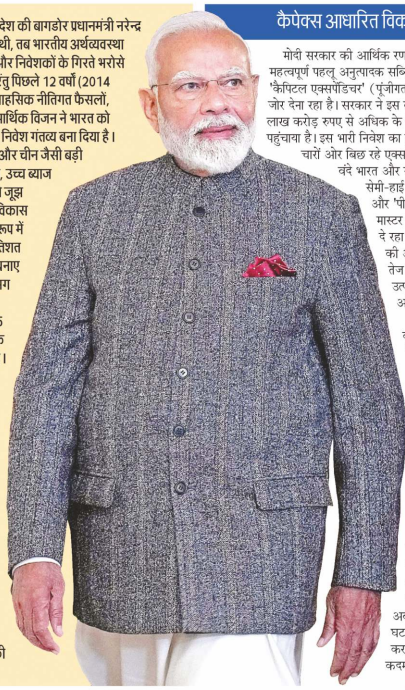

कैपेक्स आधारित विकास और मेक इन इंडिया की ऊंची छलांग

मोदी सरकार की आर्थिक रणनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुत्पादक सब्सिडियों के बजाय 'कैपिटल एक्सपेंडिचर' (पूंजीगत व्यय या कैपेक्स) पर जोर देना रहा है। सरकार ने इस बजटीय खर्च को 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया है। इस भारी निवेश का सीधा परिणाम देश के चारों ओर बिछ रहे एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, वंदे भारत और नमो भारत जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के जाल और 'पीएम गतिशक्ति' नेशनल मास्टर प्लान के रूप में दिखाई दे रहा है। जब देश में माल की आवाजाही सस्ती और तेज होगी, तो भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

इसी बुनियादी ढांचे की मजबूती के साथ 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान ने देश की विनिर्माण का वैश्विक महाशक्ति बना दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर (चिप निर्माण) जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों में मिल रही सफलता यह साबित करती है कि भारत अब आयात पर निर्भरता घटाकर दुनिया को निर्यात करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट और खिलौना उद्योग से लेकर मोबाइल उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक बनना देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ऊंची छलांग की कहानी बयां करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल 12 वर्षों का यह कार्यकाल भारत के आर्थिक कायाकल्प का स्वर्णिम अध्याय है। एक नाजुक और अस्थिर अर्थव्यवस्था के दौर से निकलकर आज भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के मुहाने पर खड़ा है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि सही नीतियां और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति क्या चमत्कार कर सकती हैं। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, जीएसटी 2.0 का स्थायित्व, घरेलू निवेशकों का शेयर बाजार पर अटूट भरोसा और पीएलआई स्कीम के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की रणनीतियों ने भारत के आर्थिक मॉडल को पूरी दुनिया में एक मिसाल बना दिया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मंदी के बादलों के बीच भी भारत की वह सुदृढ़ स्थिति देश के उद्यमियों, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के सामर्थ्य का सम्मान है। विरासत और आधुनिकता के समन्वय के साथ, यह मजबूत आर्थिक नींव देश को केवल 5 ट्रिलियन डॉलर ही नहीं, बल्कि आजादी के शताब्दी वर्ष तक 'विकसित भारत @ 2047' के महान लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर पूरी गति से आगे बढ़ा रही है।

नीतिगत निरंतरता और टैक्स स्लैब में ऐतिहासिक राहत का गणित

भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यहां का विशाल घरेलू बाजार और मजबूत मध्यम वर्ग है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह भली-भांति समझा कि यदि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, तो मध्यम वर्ग के हाथों में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा होना अनिवार्य है। इसी सोच के तहत पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक और क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। नई कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। टैक्स छूट की सीमा बढ़ने से मध्यम वर्ग के हाथों में खर्च करने योग्य पैसा बढ़ा है, जिसने बाजार में मांग और उपभोग को नई रफ्तार दी है। करदाताओं के लिए फेसलेस असेसमेंट और आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से इतना सुगम बना दिया गया है कि जहां पहले रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वह मात्र कुछ दिनों में सीधे बैंक खातों में आ जाता है। इस पारदर्शिता ने न केवल करदाताओं का भरोसा जीता है, बल्कि देश में टैक्स बेस (कर आधार) को भी रिकॉर्ड स्तर पर विस्तृत किया है, जिससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

जीएसटी 2.0 और वन नेशन वन टैक्स से कर अनुपालन की नई क्रांति

जुलाई 2017 में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था। शुरुआती तकनीकी चुनौतियों और ढांचागत बदलावों के दौर से निकलकर आज देश 'जीएसटी 2.0' के दौर में प्रवेश कर चुका है। जीएसटी 2.0 का तात्पर्य एक अधिक परिपक्व, स्थिर और तकनीक-संचालित कर प्रणाली से है, जिसने राज्यों के बीच की आर्थिक दीवारों को पूरी तरह ढहा दिया है। यहां यह स्पष्ट करना प्रासंगिक है कि शुरुआती तकनीकी बदलावों के बाद अब देश 'जीएसटी 2.0' के दौर में है, जहां एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से टैक्स चोरी पर न केवल प्रभावी लगाम लगी है, बल्कि कर-अनुपालन बेहद आसान हो गया है। आज जीएसटी 2.0 के तहत कर की दरें तर्कसंगत और स्थिर हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर बोझ कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मासिक जीएसटी संग्रह के आंकड़ों में देखा जा सकता है। अब हर महीने औसतन 1.70 लाख करोड़ से 1.85 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह होना एक सामान्य बात हो चुकी है। इस निरंतर बढ़ते कर-राजस्व ने केंद्र और राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए भारी राजकोषीय ताकत प्रदान की है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य का मुख्य ईंधन है।

डोमेस्टिक कैपिटल को संबल और शेयर बाजार का ऐतिहासिक वैल्थ क्रिएशन

मोदी सरकार के कार्यकाल की एक सबसे बड़ी और दूरगामी उपलब्धि भारतीय शेयर बाजार का लोकतांत्रीकरण और उसका अभूतपूर्व विस्तार है। सरकार ने बैंकिंग और वित्तीय सुधारों के जरिए आम भारतीय नागरिकों में शेयर बाजार के प्रति गहरा भरोसा जगाया है। जनधन खातों, डिजिटल साक्षरता और म्यूचुअल फंड के नियमों को पारदर्शी बनाने का परिणाम है कि आज भारतीय शेयर बाजार केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों के भरोसे नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों छोटे और मध्यम वर्गीय 'रिटेल इनवेस्टर्स' इसकी सबसे मजबूत रीढ़ बन चुके हैं। हर महीने देश के वेतनभोगी वर्ग द्वारा किया जाने वाला रिकॉर्ड एसआईपी निवेश इस बात का गवाह है कि भारत की घरेलू पूंजी अब देश के औद्योगिक विकास का आधार बन रही है। इसके साथ ही, मोदी सरकार के कार्यकाल में शेयर बाजार के सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी ने ऐतिहासिक शिखरों को छुआ है। सेबी को मजबूत कर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पूर्ण पारदर्शिता लाना, दुनिया की सबसे तेज टी+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करना और आईपीओ प्रक्रिया को पारदर्शी व सुगम बनाने जैसे नीतिगत कदमों ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले बाजारों में शुमार कर दिया है। इस कड़े विनियामक ढांचे और आर्थिक सुदृढ़ता के कारण पिछले 12 वर्षों में निवेशकों की संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसने देश के भीतर वेल्थ क्रिएशन की एक नई संस्कृति को जन्म दिया है।

बैंकिंग सेक्टर का कायाकल्प और वैश्विक मंदी के बीच ब्राइट स्पॉट

वर्ष 2014 से पहले भारतीय बैंकिंग प्रणाली एनपीए के मलबे के नीचे दबी हुई थी। मोदी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे सख्त कानून लागू किए और सरकारी बैंकों का रणनीतिक विलय करके उन्हें वैश्विक स्तर के मजबूत बैंकों में तब्दील किया। परिणाम यह हुआ कि आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अपने इतिहास के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है। बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर एक दशक के सबसे निचले स्तर यानी 3 प्रतिशत से नीचे आ चुका है। बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत हो चुकी है कि वे अब उद्योगों को बड़ा कर्ज देने के लिए पूरी तरह सक्षम और लालायित हैं, जिससे देश के क्रेडिट ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है।

यही कारण है कि जब अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी महाशक्तियां मंदी, महंगाई और बैंकिंग संकट से जूझ रही हैं, तब भारत अपनी 'सप्लाई-साइड रिफॉर्म्स' और स्वतंत्र आर्थिक नीतियों के दम पर लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी शीर्ष वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने बार-बार भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का 'अकेला ब्राइट स्पॉट' और वैश्विक विकास का मुख्य 'ग्रोथ इंजन' माना है। इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना बना दिया है।

आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक चित्र (तब बनाम अब)

आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक	वर्ष 2014 की स्थिति	वर्ष 2026 की स्थिति
भारत की नॉमिनल जीडीपी	लगभग $1.85 ट्रिलियन (10वां स्थान)	लगभग $4.15 ट्रिलियन (5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था)
औसत मासिक जीएसटी संग्रह	लागू नहीं (अप्रत्यक्ष करों में बिखराव)	1.70 लाख करोड़ रु .से 1.85 लाख करोड़ रु .(जीएसटी 2.0)
पूंजीगत व्यय	लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए	11.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक (ऐतिहासिक उच्च स्तर)
बैंकों का ग्रॉस एनपीए	10% से अधिक (बैंकिंग संकट का दौर)	3% से नीचे (एक दशक का सबसे निचला और मजबूत स्तर)
भारतीय शेयर बाजार	विश्व में शीर्ष देशों से काफी पीछे	दुनिया के शीर्ष 5 बाजारों में शामिल, रिकॉर्ड रिटेल इनवेस्टर्स की भागीदारी

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. विजय कलंत्री
चेयरमैन: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई
अध्यक्ष : एमवीआईआरडीसी